दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, रविवार 04 जुलाई 2021 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-03, अंक- 274

महत्वपूर्ण एवं खास

कोवैक्सिन कोरोना के खिलाफ 78 फीसदी तक असरदार

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोरोना वैक्सीन की दूसरी लहर की रफ्तार कम हुई है। लेकिन इसके इतर डेल्टा वैरिएंट ने लोगों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। इस बीच भारत बायोटेक ने शनिवार को कोवैक्सिन के तीसरे चरण के ट्रायल के परिणाम जारी किए हैं, जिनमें दावा किया है कि यह वैक्सीन कोरोना संक्रमण के खिलाफ 78 फीसदी तक प्रभावी है। वहीं कोरोना के डेल्टा वैरिएंट के खिलाफ 65.2 फीसदी तक असरकारी है। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक कंपनी ने कोवैक्सिन के तीसरे चरण के ट्रायल के परिणाम जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि कोरोना वैक्सीन कोवैक्सिन भारत में कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे बड़ा हथियार साबित होगी। भारत बायोटेक ने तीसरे चरण के ट्रायल में 130 कोरोना संक्रमण मरीजों को भी शामिल किया। इनका विश्लेषण करने के बाद कंपनी ने कहा कि कोरोना संक्रमण के खिलाफ कोवैक्सिन 77.8 फीसदी तक असरदार रही है। भारत बायोटेक के दावे के मुताबिक कोरोना वैक्सीन कोवैक्सिन के प्रभावकारिता के विश्लेषण से पता चला है कि गंभीर मरीजों पर यह 93.4 फीसदी तक प्रभावी रही है। वहीं इन दिनों दुनिया भर में कोहराम मचाने वाले कोरोना के डेल्टा वैरिएंट के खिलाफ यह 65.2 तक प्रभावी है। इससे पहले शीर्ष अमेरिकी स्वास्थ्य संस्था नेशनल इंस्टिट्यूट्स ऑफ हेल्थ (एनआईएच) ने माना था कि कोवैक्सिन डेल्टा ही नहीं अन्य दूसरे वैरिएंट के खिलाफ भी कारगर है। एनआईएच ने अपने एक बयान में कहा कि कोवैक्सिन की डोज लेने वाले लोगों के शरीर से लिए गए ब्लड सीरम की स्टडी करने पर पाया गया कि वैक्सीन से बनी एंटीबॉडीज सार्स-कोव-2 के अल्फा वैरिएंट और डेल्टा वैरिएंट को पूरी तरह निष्क्रीय कर देती है। अल्फा वैरिएंट सबसे पहले यूके में जबकि डेल्टा वैरिएंट भारत में मिला था।

ऑनर किलिंग में पिता ने की प्रेमी युगल की हत्या

मेरठ (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश के मेरठ में आनर किलिंग की एक घटना में एक व्यक्ति ने अपनी बेटी और उसके प्रेमी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि खरखौदा क्षेत्र के गांव बधौली निवासी 18 वर्षीय आरिफ का पड़ोस की रहने वाली अपने ही धर्म की एक किशोरी से पिछले कुछ माह से प्रेम प्रसंग चल रहा था। शुक्रवार रात आरिफ के मस्जिद से नमाज पढ़कर वापस लौटने के दौरान छत पर खड़ी प्रेमिका से उसकी इशारे बाजी होने लगी। यह देखकर किशोरी का पिता तौसीन आपे से बाहर हो गया और तमंचे से चार गोलियां आरिफ को मारीं और फिर घर जाकर बेटी को दो गोलियां मार दीं, जिससे दोनों की ही मृत्यु हो गई। सरेआम इस वारदात को अंजाम देने से गांव में भगदड़ मच गई और किसी ने भी हत्यारे को पकड़ने की हिम्मत नहीं की। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो किशोरी जिंदा थी और उसने पिता के विरुद्ध बयान दिया जिस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और बाद में उसने अपना जुर्म भी कुबूल कर लिया। पुलिस ने दोनो शवों को कब्जे में लेकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिये भिजवा दिया है।

देश में कोरोना संक्रमण... 24 घंटे में 44,111 नए मामले, 738 की मौत

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर ढ़लान पर है, लेकिन दैनिक मामलों में उतार-चढ़ाव का सिलसिला जारी है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 44,111 नए मामले दर्ज किये गये, जबकि संक्रमण से 738 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही देश में अब तक कोरोना के कारण चार लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। राहत की बात यह है कि देश में कोरोना को मात देने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है और सक्रीय मरीजों की संख्या भी लगातार घट रही है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को जारी आंकड़ो के मुताबिक पिछले 24 घंटे में मिले 44,111 नए मरीजों के बाद देश में अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 3,05,02,362 हो गयी। जबकि इस दौरान 738 लोगों की मौत के साथ देश में संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,01,050 हो गयी है जो 86 दिनों में सबसे कम है। आंकड़े के अनुसार 97 दिन बाद देश में उपचाराधीन रोगियों की संख्या पांच लाख से कम 4,95,533 दर्ज की गयी जो संक्रमण के कुल मामलों का 1.62 प्रतिशत है। कोविड-19 से ठीक होने की राष्ट्रीय दर सुधरकर 97.06 प्रतिशत हो गयी है। पिछले 24 घंटे के दौरान उपचाराधीन मामलों में 14,104 की कमी आयी है। बृहस्पतिवार को 18,76,036 नमूनों की जांच की गयी। देश में अब तक 41,64,16,463 नमूनों की कोविड-19 संबंधी जांच हुई है। जबकि दैनिक संक्रमण दर 2.35 प्रतिशत है। यह लगातार 26वें दिन पांच प्रतिशत से कम है। साप्ताहिक संक्रमण दर 2.50 प्रतिशत है। देश में अब तक 2,96,05,779 मरीज स्वस्थ हुए हैं जबकि मृत्यु दर1.31 प्रतिशत है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत टीके की अब तक 34.46 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं।

महाराष्ट्र में ज्यादा मौतें- आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में जिन 738 लोगों की मौत हुई है, उनमें महाराष्ट्र के 156 लोग, केरल के 146 लोग, तमिलनाडु के 97 लोग और कर्नाटक के 88 मरीज शामिल थे। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक संक्रमण से कुल 4,01,050 लोगों की मौत हुई है, जिनमें महाराष्ट्र के 1,22,353, कर्नाटक के 35,222, तमिलनाडु के 32,818, दिल्ली के 24,983, उत्तर प्रदेश के 22,616, पश्चिम बंगाल के 17,758 और पंजाब के 16,086 मरीज शामिल थे।

ऐसे चला संक्रमण का प्रकोप- देश में पिछले साल सात अगस्त को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और पांच सितम्बर को 40 लाख से अधिक हो गई थी। वहीं, संक्रमण के कुल मामले 16 सितम्बर को 50 लाख, 28 सितम्बर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख, 20 नवम्बर को 90 लाख के पार हो गए। देश में 19 दिसम्बर को ये मामले एक करोड़ के पार, चार मई को दो करोड़ के पार और 23 जून को तीन करोड़ के पार चले गए थे।

पुष्कर सिंह धामी होंगे उत्तराखंड के नए सीएम

देहरादून (आरएनएस)। उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत से बनी भाजपा की सरकार का कार्यकाल पूरा होने से लगभग 8 महीने पहले तीसरी बार नए मुख्यमंत्री के रूप में विधायक पुष्कर सिंह धामी को विधायक का चुन लिया गया। वह आज शाम को नए पद की शपथ ले सकते हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की उपस्थिति में अपराह्न तीन बजे विधानमंडल दल की बैठक पार्टी के प्रदेश कार्यालय में शुरू हुई। इसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत सहित भाजपा सांसद और विधायक भी उपस्थित रहे। लगभग 30 मिनट तक चली इस बैठक में खटीमा से विधायक धामी को विधायक दल का नेता सदन चुन लिया गया। तोमर ने बैठक कक्ष के बाहर एकत्रित संवाददाताओं को इसकी जानकारी दी। धामी को नेता सदन चुने जाते ही फूल-मालाओं से लाद दिया गया। धामी ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है और वे कल सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। उल्लेखनीय है कि पौड़ी संसदीय क्षेत्र से सांसद और निवर्तमान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शुक्रवार देर रात्रि मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था। इसका कारण उनको विधायक न होना था। संवैधानिक कारणों से राज्य सरकार का कार्यकाल एक वर्ष से कम होने के कारण विधानसभा का उपचुनाव नहीं कराया जा सकता था। इससे पूर्व, 9 मार्च को तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर तीरथ मुख्यमंत्री बनाए गए थे। 46 साल के धामी बीजेपी के युवा नेता हैं और उत्तराखंड में अभी तक बने सभी मुख्यमंत्रियों में सबसे युवा हैं।धामी का जन्म साल 16 सितंबर, 1975 को राज्य के सीमांत जिले पिथौरागढ़ की तहसील डीडीहाट के टुण्डी गांव में हुआ है।

सरकार की सख्ती के बीच सोशल मीडिया से हटे आपत्तिजनक पोस्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सरकार की सख्ती का असर दिखने लगा है। गूगल, फेसबुक और इंस्टाग्राम ने अब अपने प्लेटफॉर्म से आपत्तिजनक पोस्ट हटाए हैं। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने नये आईटी नियमों के तहत गूगल, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया मंचों द्वारा आपत्तिजनक पोस्ट स्वतः हटाने पर अपनी पहली अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए उनकी तारीफ की।

गौरतलब है नये सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों के तहत 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं वाले बड़े डिजिटल मंचों को हर महीने अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करनी होगी जिसमें प्राप्त शिकायतों और उन पर की गयी कार्रवाई का उल्लेख किया गया हो। रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट किया कि गूगल, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मंचों को नये आईटी नियमों का पालन करते देखना सुखद है। उनके द्वारा नये आईटी नियमों के अनुसार आपत्तिजनक पोस्ट को स्वतः हटाने पर पहली अनुपालन रिपोर्ट का प्रकाशन पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम है। अब इन तीनों मंचों द्वारा अनुपालन रिपोर्ट जारी करने से ट्विटर पर दबाव बढ़ सकता है जिसका नये नियमों को लेकर केंद्र सरकार के साथ गतिरोध बना हुआ है। सरकार ने देश के नये आईटी नियमों का अनुपालन नहीं करने पर तथा इसके लिए अधिकारियों की नियुक्ति नहीं करने पर ट्विटर से नाराजगी जताई थी। फेसबुक ने अपनी पहली मासिक अनुपालन रिपोर्ट में कहा कि उसने देश में 15 मई से 15 जून के बीच उल्लंघन की 10 श्रेणियों में तीन करोड़ से अधिक सामग्रियों पर कार्रवाई की।

सीजफायर समझौते के बाद नहीं हुई घुसपैठ :सेना प्रमुख

» ड्रोन से निपटने को विकसित हो रहीं क्षमताएं

नई दिल्ली (आरएनएस)। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने बड़ा बयान दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम समझौता होने के बाद नियंत्रण रेखा पर कोई घुसपैठ नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हमारा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद रोधी और घुसपैठ रोधी मजबूत तंत्र है, शांति, सामंजस्य सुनिश्चित करने का हमारा अभियान जारी रहेगा।

सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने कहा कि घुसपैठ न होने से कश्मीर में आतंकवादियों की संख्या भी कम हुई है। उन्होंने कहा कि ऐसे तत्व हमेशा रहेंगे जो शांति एवं विकास की प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसका हमें ध्यान रखना है। सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने जम्मू वायुसेना स्टेशन पर किए गए ड्रोन हमले पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ड्रोन के आसानी से उपलब्ध होने से निश्चित तौर पर जटिलता और चुनौतियां बढ़ी हैं। हमने कुछ कदम उठाए हैं, सभी जवानों को इस खतरे से अवगत कराया गया है । खतरे से निपटने के लिए क्षमताएं विकसित की जा रही है। चाहे ये खतरे देश प्रायोजित हों या देशों ने खुद पैदा किए हों। एक विचार समूह (थिंक टैंक) में दिए गए संबोधन में जनरल नरवणे ने कहा कि सुरक्षा प्रतिष्ठान चुनौतियों से अवगत हैं और इनसे निपटने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं।

उन्होंने कहा कि हम खतरे से निपटने के लिए क्षमताएं विकसित कर रहे हैं, चाहे ये खतरे देश प्रायोजित हों या खुद देशों ने पैदा किए हों। हम गतिज और गैर गतिज क्षेत्र दोनों में ड्रोन खतरे से निपटने की क्षमताएं विकसित कर रहे हैं। जनरल नरवणे से जम्मू वायु सेना स्टेशन पर हाल में हुए ड्रोन हमले के बारे में पूछा गया था। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर हालात पर सेना प्रमुख ने कहा कि भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच फरवरी में हुए संघर्ष विराम समझौते के बाद नियंत्रण रेखा पर कोई घुसपैठ नहीं हुई।

केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार की अंतिम तैयारी पूरी, कम होगा कई मंत्रालयों का बोझ

नई दिल्ली (आरएनएस)। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले मंत्रिमंडल विस्तार की अंतिम तैयारी पूरी हो गई है। असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल को शनिवार को दिल्ली तलब कर लिया गया, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी राजधानी में ही रहने के लिए कहा गया है।

सूत्रों का कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार में व्यापक फेरबदल होगा। वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिमंडल में 53 मंत्री हैं। संविधान के मुताबिक अधिकतम 81 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस हिसाब से मंत्रिमंडल में 28 और लोगों को समायोजित किया जा सकता है। विस्तार में एनडीए के सहयोगी दलों में से अपना दल और अन्नाद्रमुक को भी जगह मिलेगी। लेकिन जदयू को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। सूत्रों के मुताबिक, मंत्रिमंडल विस्तार में एक दर्जन मंत्रियों की छुट्टी होगी और करीब इतनी ही संख्या में मंत्रियों के विभागों में फेरबदल किया जाएगा। चूंकि वर्तमान में 28 मंत्रियों को नई टीम में शामिल करने का विकल्प बचा है। ऐसे में दो दर्जन नए चेहरों को भी विस्तार में टीम मोदी में जगह मिलेगी।

जदयू भी होगा शामिल- राजग के सहयोगी दल जदयू को सरकार में शामिल होने के लिए दो कैबिनेट और एक राज्य मंत्री पद देने का नया प्रस्ताव भेजा गया है। लेकिन जदयू विस्तार में शामिल होगा या नहीं, यह बिहार के सीएम नीतीश कुमार के रुख पर निर्भर करेगा। नीतीश मंत्रिमंडल में पांच पद मांग रहे हैं। उन्होंने नए प्रस्ताव को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं।

यूपी से भी आएंगे नए चेहरे- मंत्रिमंडल विस्तार पर पीएम मोदी की निगाहें उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव पर होगी। चर्चा है कि इस विस्तार के जरिए पार्टी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मतदाताओं को खास तौर पर रिझाएगी। ऐसे में रीता बहुगुणा जोशी, वरुण गांधी और रमापति राम त्रिपाठी में से किन्हीं दो को मंत्रिमंडल में जगह मिलने की चर्चा है। इसके अलावा दलित बिरादरी को संदेश देने के लिए रमाशंकर कठेरिया और मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के लिए जफर इस्लाम को मंत्री बनाए जाने की संभावनाएं भी जताई जा रही है।

नौ मंत्रियों पर अभी काम का अतिरिक्त बोझ- रामविलास पासवान और सुरेश अंगड़ी के निधन और राजग के सहयोगी रहे शिवसेना और अकाली दल के कोटे के मंत्रियों के इस्तीफे के कारण फिलहाल नौ मंत्रियों के पास अतिरिक्त मंत्रालयों का भी बोझ है। इनमें नितिन गडकरी, प्रकाश जावड़ेकर, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, हरदीप पुरी, रविशंकर प्रसाद, धर्मेंद्र प्रधान और हर्षवर्धन शामिल हैं। विस्तार में इन मंत्रियों के काम का बोझ हल्का किए जाने की चर्चा है।

कारोबारियों को सशक्त बनाने में जुटी सरकार : पीएम मोदी

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुदरा एवं थोक व्यापार को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों (एमएसएमई) के तहत लाने के फैसले को शनिवार को ऐतिहासिक करार दिया और कहा कि उनकी सरकार इस समुदाय को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। खुदरा एवं थोक व्यापार को एमएसएमई के तहत लाने के फैसले के कारण खुदरा और थोक व्यापारियों को भी बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से प्राथमिकता प्राप्त श्रेणी में ऋण उपलब्ध हो सकेगा। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने खुदरा और थोक व्यापार को एमएसएमई के तहत लाने की शुक्रवार को घोषणा की थी। इससे ये क्षेत्र भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप बैंकों की प्राथमिकता प्राप्त श्रेणी के तहत ऋण का लाभ उठा सकेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि हमारी सरकार ने खुदरा एवं थोक व्यापार को एमएसएमई में शामिल करने का ऐतिहासिक कदम उठाया है। इससे हमारे करोड़ों व्यापारियों को आसानी से ऋण मिलने में मदद मिलेगी। उन्हें कई अन्य लाभ मिलेंगे और उनके कारोबार को भी बढ़ावा मिलेगा। हम हमारे व्यापारियों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

रेप पीड़िता का नाम अदालती कार्यवाही में भी नहीं हो

» सुप्रीम कोर्ट की निचली अदालतों को दो टूक

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी अदालतों में बलात्कार पीड़िता के नाम का उल्लेख किसी कार्यवाही में भी नहीं होना चाहिए। निचली अदालतों को इस प्रकार के मामलों से निपटते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने छत्तीसगढ़ में एक सत्र अदालत के उस फैसले पर नाराजगी जताते हुए यह निर्देश दिया, जिसमें बलात्कार पीड़िता के नाम का उल्लेख किया गया था।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि यह पूरी तरह से स्थापित है कि इस प्रकार के मामलों में पीड़िता का नाम किसी भी कार्यवाही में नहीं आना चाहिए। पीठ ने कहा कि हम सत्र न्यायाधीश के फैसले पर अप्रसन्नता जताते हैं, जहां पीड़िता के नाम का उल्लेख किया गया है। पीठ ने अपने आदेश में यह बात कही और दोषी की ओर से दाखिल याचिका खारिज कर दी। याचिका में बलात्कार के मामले में उसे दोषी ठहराने के छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी। पीठ ने कहा कि मामले के तथ्य के अनुसार हम इस विशेष अवकाश याचिका पर सुनवाई नहीं करना चाहते। उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2019 के अपने फैसले में बलात्कार के मामले में दोषी ठहराए जाने के निचले आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी थी। वर्ष 2001 में दर्ज मामले में महासमुंद की सत्र अदालत ने व्यक्ति को दोषी करार दिया था। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि पीड़िता के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि यह सहमति से शारीरिक संबंध बनाने का मामला नहीं है। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने दिसंबर 2018 के अपने एक आदेश में कहा था कि दुष्कर्म और यौन प्रताड़ना के पीड़ितों के नाम और उनकी पहचान उजागर नहीं की जा सकती, भले ही उनकी मृत्यु हो चुकी हो।

राफेल विवाद : कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना

» क्या पीएम देंगे जेपीसी जांच की अनुमति : सुरजेवाला

नई दिल्ली (आरएनएस)। राफेल डील को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सीधे-सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला है। सुरजेवाला ने कहा कि रिलायंस-डसॉल्ट डील के सारे सबूत सार्वजनिक कर दिए गए हैं। मोदी सरकार और जानेमन डील (राफेल डील) अब साफ हो गई है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब संयुक्त संसदीय समिति की जांच की अनुमति देंगे। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि यह प्रथम दृष्टि में भ्रष्टाचार का आरोप है।

सुरजेवाला ने कहा कि फ्रांस में प्रथम दृष्या भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं । तो सरकार जेपीसी की जांच क्यों नहीं करवाती है। यदि दाल में कुछ काला नहीं है तो फिर जांच से सरकार को क्यों बच रही है। उन्होंने आगे कहा कि यह राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, इसलिए जेपीसी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता, जवाबदेही, भ्रष्टचार मुक्त शासन देना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है।

कांग्रेस पर भाजपा का तीखा पलटवार

वहीं कांग्रेस के आरोप पर भाजपा पलटवार किया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, कांग्रेस झूठ और मिथकों का पर्याय है। आज उन्होंने फिर से राफेल सौदे के बारे में झूठ बोला। यदि किसी देश का एनजीओ किसी आरोप के खिलाफ शिकायत करता है और उसका वित्तीय अभियोजन निकाय तदनुसार जांच का आदेश देता है, तो इसे भ्रष्टाचार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। पात्रा ने आगे कहा कि फ्रांस में राफेल सौदे को लेकर जांच होने वाली है। किसी एनजीओ ने फ्रांस की कोर्ट में शिकायत की थी, इस जांच को भ्रष्टाचार की नज़र से देखना उचित नहीं है, लेकिन इस मुद्दे पर राहुल गांधी जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं वह दुखद है।